प्रेस विज्ञप्ति

18/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सहसपुर, देहरादून, उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पता चला कि दीप्ति रावत पत्नी हरक सिंह रावत और लक्ष्मी सिंह राणा ने बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, स्वर्गीय सुशीला रानी और अन्य व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश के परिणामस्वरूप भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत करने में कामयाब रहे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद, सुशीला रानी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, सहसपुर, देहरादून स्थित ज़मीनों की दो पावर ऑफ़ अटॉर्नी पंजीकृत कराई। इसके अलावा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक, हरक सिंह रावत के एक निकट सहयोगी, बीरेंद्र सिंह कंडारी ने इन ज़मीनों को दीप्ति रावत और लक्ष्मी सिंह राणा को उस क्षेत्र में प्रचलित सर्किल दरों से काफ़ी कम कीमत पर बेच दिया। दीप्ति रावत द्वारा खरीदी गई ज़मीनें अब दून इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस (श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अधीन संचालित) का हिस्सा हैं, जिसका नियंत्रण हरक सिंह रावत के परिवार और मित्रों के पास है।

इससे पहले, जनवरी 2025 में, ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें लगभग 101 बीघा ज़मीन, जिसकी कीमत 6.56 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक) है, को कुर्क किया गया था, जिसमें इस मामले में जिला-देहरादून में ज़मीन के 2 टुकड़े भी शामिल हैं।

आगे की जाँच जारी है।